भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के पश्चात आयोजित पत्रकार वार्ता का संशोधित प्रतिलेख: 6 जून, 2025 (शुक्रवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:
श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामिनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. ए. आर. जोशी - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक:
श्री पुनीत पंचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संजय मल्होत्रा:
नमस्कार और शुभ दोपहर।

पुनीत पंचोली:
नमस्ते और शुभ अपराह्न। भारतीय रिजर्व बैंक की इस वित्त वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति के पश्चात आयोजित पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है।
मित्रो, आज हमारे साथ गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर - श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे., और डॉ. पूनम गुप्ता उपस्थित हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए डॉ. गुप्ता का, उप गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण करने के पश्चात, इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ।
हमारे साथ कार्यपालक निदेशक, डॉ. राजीव रंजन और डॉ. अजीत जोशी, तथा रिजर्व बैंक के अन्य मित्र भी उपस्थित हैं। प्रारंभ करने से पूर्व, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें।
कृपया प्रति व्यक्ति केवल एक प्रश्न पूछें, ताकि सभी को अवसर मिल सके, और यदि समय अनुमति दे, तो हम आगे चलकर दूसरा प्रश्न ले सकते हैं। प्रश्न पूछते समय, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सामने लगा माइक्रोफोन चालू हो, क्योंकि इस प्रसारण को सुन रहे लोगों को यहाँ की कार्यवाही सुनाई दे सके। प्रश्न पूछने के पश्चात, हस्तक्षेप से बचने के लिए कृपया इसे बंद कर दें।

महोदय, आज मीडिया के 23 प्रतिभागी उपस्थित हैं, और आपकी अनुमति से, मैं नाम पुकारूँगा। मैं लता से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूँ।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

धन्यवाद, सर। सीएनबीसी-टीवी18 से लता। गवर्नर, इस अवसर और ऐसी नीति प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने हमें कई सुर्खियाँ दी हैं। मैं चलनिधिन के मुद्दे पर कुछ स्पष्टता चाहती थी। पिछले कुछ सप्ताहों में, मांग दर रेपो दर पर नहीं था। आपने पर्याप्त चलनिधि प्रदान की, और मांग दररेपो दर से 25 आधार अंक कम था।

अब जब आपने 50 आधार अंक की कटौती की है, क्या आप चलनिधि का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि मांग दरको रेपो दर के अधिक निकट लाया जा सके, जिसका अर्थ है कि आप अधिक वीआरआरआर (विपरीत रेपो) करेंगे? अथवा क्या विपरीत रेपो को निलंबित करना होगा, क्योंकि आपकी 40 अरब अमेरिकी डॉलर की अधिविक्रय की स्थिति की परिपक्वता होने वाली है? अतः यदि आप चलनिधि पर थोड़ी और जानकारी दे सकें।

और नीति के रुख के संबंध में, क्या बाजार द्वारा एक विस्तारित विराम मानना उचित है? अथवा, यदि आप सकारात्मक वास्तविक ब्याज दर 1.4 से 1.9 प्रतिशत मान रहे हैं, तो 3.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के साथ, आपके पास अभी भी कटौती का अवसर है। अतः क्या बाजार को यह मानना चाहिए कि विराम के पश्चात भी अंतिम दर (टर्मिनल दर) में और कमी आ सकती है?

संजय मल्होत्रा:

सबसे पहले, आप सभी का हमेशा की तरह यहाँ आने और हमारे संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। आपने एक प्रश्न में तीन प्रश्न पूछे हैं, लेकिन हम सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम चलनिधि के साथ क्या करते हैं? हम वास्तव में मांग दर को कहाँ बनाए रखते हैं? आज मांग दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के निचले छोर पर मंडरा रहा है, जैसा कि यह कल तक था। यह लगभग 5.75% पर था।

क्या हम अब इसे 5.25% पर बनाए रखेंगे या नीतिगत दर जो कि 5.5% है, पर? जैसा कि मैंने कहा, हम देखेंगे कि स्थिति कैसे विकसित होती है। निस्संदेह चलनिधि प्रचुर मात्रा में है, और यदि हम कोई वीआरआरआर नहीं करते हैं, तो यह 5.25% पर ही रहेगी। यदि हम वीआरआरआर करते हैं, तो हम राशि के आधार पर इसे कहीं भी ला सकते हैं। अतः हम देखेंगे कि स्थिति कैसे विकसित होती है और हम निर्णय लेंगे। हमने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया है। हम निर्णय लेंगे और आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मैं आपको बहुत सटीक उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन नीतिगत दर को 5.5% पर और रुख को अब तटस्थ

करने के साथ, यह सब निश्चित रूप से ध्यान में आएगा। हम निर्णय लेंगे कि हम मांग दर को कहाँ रखने का प्रयास करेंगे।
दूसरा प्रश्न यह है कि हम अंतिम दर को कहाँ देखते हैं? मौद्रिक नीति समिति ने विवरण और संकल्प में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने रुख को निभावकारी से तटस्थ में बदल दिया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मौद्रिक नीति के लिए वास्तव में बहुत सीमित स्थान शेष है। आप वर्तमान परिस्थितियों से अवगत हैं, जिसमें विकास दर लगभग 6.5% है, मुद्रास्फीति का अनुमान हम इस वर्ष के लिए 3.7% लगा रहे हैं, और अगले वर्ष यह 4% से ऊपर, लगभग 4.5% रहेगी। यदि ये अनुमान सही ठहरते हैं, तो एमपीसी का कहना है कि बहुत सीमित स्थान शेष है, इसीलिए हमने अब रुख को तटस्थ कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति ने यह भी कहा है कि हम आंकड़ों की निगरानी जारी रखेंगे, और विशेष रूप से अनिश्चितताओं को देखते हुए, अब हम किस दिशा में बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि आंकड़े क्या संकेत देते हैं। एक तीसरा प्रश्न भी था। बस इतना ही। धन्यवाद। मैंने सभी का उत्तर दे दिया है।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:
यही मैं चाहती थी। हाँ। यदि आप मुझे एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दें, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ?

संजय मल्होत्रा:
हाँ। हम बाद में वापस आएंगे और देखेंगे, यदि समय हो तो।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला, हम श्री मयूर शेट्टी को द टाइम्स ऑफ इंडिया से बुलाएंगे।

मयूर शेट्टी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:
गवर्नर, आपने अनिश्चित वातावरण के बारे में बात की, और बहुत सी अनिश्चितता अमेरिकी प्रशासन के व्यवहार से आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप डॉलर संपत्तियों में भी काफी अस्थिरता आ रही है। इसे देखते हुए, आप विदेशी मुद्रा भंडार के पुनर्निर्माण और विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे?

संजय मल्होत्रा:
देखिए, वहाँ हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। यह बहुत सुसंगत रही है। हम किसी भी कीमत, किसी भी स्तर, या किसी भी दायरे को प्रबंधित या लक्षित नहीं करते हैं, आप इससे अवगत हैं। यदि

कोई असामान्य अस्थिरता होती है - यह एक मानक उत्तर है - तो हम उसका मुकाबला करने का प्रयास करते हैं, और हम कीमतों को बाजार द्वारा निर्धारित होने देते हैं।

अब, यह प्रश्न, और मुझे लगता है कि लता ने भी इसकी ओर संकेत किया था, और वह तीसरा बिंदु जो आपने उल्लेख किया था, वह इस 40 अरब अमेरिकी डॉलर आदि के बारे में है। हम इसके बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं हैं। भले ही आप उस 625 अरब अमेरिकी डॉलर को बाहर निकाल दें। यदि हम 65 अरब अमेरिकी डॉलर को बाहर निकाल दें, जिसमें वह भी शामिल है जो एक वर्ष में आ रहा है, तो हम इसके बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं हैं। यह एक बहुत ही सहज स्तर है। हाँ, यदि अवसर मिलते हैं और हम भंडार का निर्माण कर सकते हैं, तो वह होगा, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम अत्यधिक चिंतित होंगे। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब, मी श्री अनुराग शाह से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूँ। ईटी नाउ स्वदेश से अनुराग शाह।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

धन्यवाद, सर। धन्यवाद। सर, आपने इतना बड़ा आश्चर्य दिया है, इसलिए मेरे पास जो मुख्य प्रश्न था, उसे मैं बाद में पूछूंगा। सर, आज की घोषणा का उद्देश्य क्या है, और आप व्यापक रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं?

संजय मल्होत्रा:

व्यापक रूप से, संदेश यह है कि मुद्रास्फीति काफी हद तक नियंत्रण में है, और हम यह मान सकते हैं कि हमने यह युद्ध जीत लिया है। यही संदेश है, क्योंकि हमने अपने अनुमान में मुद्रास्फीति को 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। इसी तरह, विकास दर का अनुमान 6.5% है। यह अच्छा है, लेकिन सुधार के लिए अभी भी गुंजाइश है। अतः, हमें जो भी करना है, हमारा मानना है कि हमें इसे निर्णायक रूप से और सही समय पर करना चाहिए।

और मुझे लगता है कि इस अनिश्चित वातावरण में जो निश्चितता है, उसकी हमें बाजारों, बैंकों और अर्थव्यवस्था को देने की निश्चित रूप से आवश्यकता थी। इसीलिए, जैसा कि आपने देखा, मुद्रास्फीति नियंत्रण समिति (मौद्रिक नीति समिति) ने कहा कि हमने अग्रिम कार्रवाई है, ताकि यह निश्चितता रहे कि हाँ, हमें 50 आधार अंक की कटौती करनी है, इसलिए हमने इसे एक ही समय में कर दिया। इसी तरह, यदि हम चाहते तो प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की घोषणा 4 महीने बाद भी कर सकते थे। हमने इसे आज ही घोषित किया है, ताकि लोगों और बैंकों को यह आश्वासन मिले कि चलनिधि जो हमने कही है, वह निश्चित है, लेकिन इसे कार्यों में भी परिवर्तित किया जाना चाहिए। अतः, हमने उन्हें कार्यों में भी परिवर्तित कर दिया है। जैसे कि हमने सीआरआर की घोषणा आज ही कर दी है। जितनी अधिक

निश्चितता होगी, हमारा उतना ही अधिक विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बल मिलेगा। और यही हमारा संदेश है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, यही हमारा मुख्य संदेश है, हम इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि हमें मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहिए, और हम इसे अंकुश में रखें। और जो भी लक्ष्य हमें दिया गया है; हमें उसकी ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा होता है, तब हमें विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यही हमने किया है।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:
जिस रुख को आपने पिछली नीति में बदला था, तटस्थ से आप निभावकारी (एकमोडेटिव) पर आए थे। और इस बार, उसी नीति में, आप उसी रूख पर वापस चले गए। तो क्या आप गलत संदेश नहीं दे रहे हैं?

संजय मल्होत्रा:
गलत संदेश, मैं समझा नहीं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। यह हमारे मन में भी था, कि हमने पिछली बार इसे निभावकारी बना दिया था। हमारे पास विकल्प था कि हमें इसे निभावकारी ही रखना चाहिए था। हम बार-बार कह रहे थे कि यह (रुख)निभावकारी है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। अतः, कार्रवाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और हम जो भी बात कर रहे हैं उसे कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे इरादों के बयान थे - निभावकारी केवल एक इरादा था। यदि हम इसे नहीं बदलते, केवल निभावकारी ही रखते, तो क्या यह बेहतर होता? या हमें यह निश्चितता देनी चाहिए कि हाँ, जो कुछ भी हमने आपको निभावकारी होने का वादा किया था, कि हम दर में कटौती करेंगे, हम इसे निर्णायक रूप से कम करेंगे। हमने वह किया है, और हमने रुख को तटस्थ कर दिया है।
आज की परिस्थितियों में, स्थिति ऐसी है कि नीतिगत दरों को कम करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है, जैसा कि मौद्रिक नीति समिति ने नोट किया, बहुत कम गुंजाइश है। अतः, बहुत सीमित स्थान है, इसलिए नीतिगत दरों में और कटौती के लिए बहुत कम गुंजाइश शेष रह जाती है। यही पूरा संदेश है जो हम देना चाहते थे, इसीलिए हमने इसे तटस्थ रखा है।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अब हम मेज के इस ओर बढ़ते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से श्री मनोजित साहा।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:
नमस्ते। शुभ अपराह्न। धन्यवाद, पुनीत जी। फिर से उसी रूख के संदर्भ में, इस नीति में कई आश्चर्य थे। सबसे आश्चर्यजनक भाग रूख है। जैसा कि आपने पिछली नीति में कहा था कि

निभावकारी का अर्थ है कि दरें कम हो सकती हैं या वहीं रह सकती हैं। तो, क्या तटस्थ का अर्थ यह होगा कि दरें बढ़ सकती हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन एक लंबा विराम रहेगा? और क्या रूख पर कोई मतदान हुआ था, यदि आप साझा कर सकें?

संजय मल्होत्रा:

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही अर्थ है। हमने पिछले मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य में इसे स्पष्ट किया था कि तटस्थ का अर्थ है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। यदि विकास कमजोर होता है, तो इसका अर्थ हो सकता है कि यह नीचे जाएगा। यदि विकास अच्छा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इसका अर्थ हो सकता है कि रेपो दर, यानी नीतिगत दर, बढ़ सकती है। अतः, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मुद्रास्फीति और विकास दोनों पर आंकड़े कैसे सामने आते हैं।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

क्या इस बार रूख पर कोई मतदान हुआ था?

संजय मल्होत्रा:

रूख पर, देखिए, हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून मतदान को अनिवार्य नहीं बनाता है। इस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई, क्योंकि हमें एक अहसास दिलाने की आवश्यकता थी, हमें बाजार सहभागियों को एक मार्गदर्शन देना था। और इसलिए, इस पर चर्चा हुई, और सभी 6 मौद्रिक नीति समिति सदस्यों का मत था कि हमें इसे तटस्थ में बदल देना चाहिए। अतः, कोई मतदान नहीं हुआ, लेकिन सभी मौद्रिक नीति समिति सदस्यों का यह मत है कि आगे चलकर रूख को समायोजक से बदलकर तटस्थ किया जाना चाहिए।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

साथ ही, यदि आप बस एक और बात जोड़ सकें। क्या आप अब तक हुई मौद्रिक संप्रेषण से संतुष्ट हैं?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि पिछले रुझानों को देखते हुए, संप्रेषण बहुत तेजी से हुआ है। वास्तव में, मनी मार्केट में आप भारी संप्रेषण देख सकते हैं - हमने जितना किया है उससे अधिक, मनी मार्केट में 50 आधार अंक से अधिक, विशेष रूप से अल्पकालिक स्तरों पर। और ऋण पक्ष पर भी हमें अब कुछ प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में, जमा दरों में कमी आई है - अधिकांश बैंकों द्वारा खुदरा और थोक दोनों में, लगभग 40 आधार अंक। वहां औसतन लगभग 27 आधार अंक की कमी हुई है। बकाया ऋण पर ऋण पक्ष में 17 आधार अंक की कमी हुई है। और नए ऋणों के संदर्भ में, यह थोड़ा धीमा है, लेकिन यह शुरू हो गया है, हमारे पास

मौजूद आंकड़ों के अनुसार यह लगभग 6 आधार अंकहै। अतः, यह धीमा है, लेकिन अन्य बार की तुलना में यह बहुत तेज है।
आमतौर पर, इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती के बाद केवल 4 महीने ही हुए हैं। अतः, 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले, यदि जमा पक्ष पर 27 आधार अंक, बकाया ऋण पक्ष पर 17 आधार अंक, और नए ऋणों पर 6 आधार अंक की कमी हुई है, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा संप्रेषण है। हालांकि, हमें इसे और तेज करने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने अपनी कुछ कार्रवाइयों को अग्रिम स्तर पर किया है।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:
बहुत-बहुत धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगला, हम एनडीटीवी प्रॉफिट से श्री विश्वनाथ नायर को बुलाएंगे।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:
नमस्ते गवर्नर। वास्तव में कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान के संबंध में है, जो बदला नहीं है, अनुमान बिल्कुल नहीं बदले हैं। आपने जो कुल 100 आधार अंक की दर कटौती की है, उससे आप किस प्रकार की विकास वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप, क्या वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोई संशोधन होगा? और दूसरा भाग स्वयं रूख पर है। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, अतीत में यह आलोचना रही है कि रूख अधिक या कम बेमानी होता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार 'निभाव को हटाना' कहते रहे, लेकिन यह एक लंबित विराम था। क्या इसे फिर से प्रासंगिक बनाने का यह एक तरीका है?

संजय मल्होत्रा:
अतः, आपका पहला प्रश्न यह है कि इसका विकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट रूप से, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह आकलन करना अत्यंत कठिन होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण दरों तक और फिर वास्तविक अर्थव्यवस्था तक यह संप्रेषण कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास के अनुसार, इसमें न्यूनतम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम निश्चित रूप से इसे त्वरित करना चाहेंगे, लेकिन हमें इसका प्रभाव केवल बाद के अर्ध भाग में ही दिखाई देगा। अतः, इस वर्ष के लिए, संख्याओं के संदर्भ में, विशेष रूप से जब इतनी अधिक अनिश्चितता है, हम आपको यह बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि यह सकल घरेलू उत्पाद की संख्याओं को किस हद तक प्रभावित करेगा।

आपके दूसरे प्रश्न पर, मैं वास्तव में अतीत के बारे में नहीं बोल सकता कि क्या हुआ, लेकिन हमारी नीति बहुत, बहुत स्पष्ट होगी; हम जो भी कह रहे हैं, हमारा उसका पूरा-पूरा आशय वही है, और आप इसे लगातार अनुभव करते रहेंगे।
यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चाहे वह अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, इसका बहुत कुछ आंकड़ों पर निर्भर करता है। अतः, यदि आंकड़े बदलते हैं, तो भले ही वह समायोजक हो या कसने वाला, इसका यह आवश्यक अर्थ नहीं निकलता कि अगली नीति में ही आप इसे कस लेंगे या नीतिगत दर को कम करेंगे। इसका ऐसा अर्थ नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आंकड़े वास्तव में कैसे आ रहे हैं और वह आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं। अतः, यदि वह आंकड़े यह मांग करते हैं कि आपको वहीं रुकना है, भले ही वह समायोजक हो, तो वैसे ही किया जाएगा।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगली बारी है रॉयटर्स से सुश्री स्वाति भट्ट की।

स्वाति भट्ट, रॉयटर्स:
धन्यवाद, पुनीत सर। सर, मैं बस यह समझना चाहती थी कि आपने दर कटौती को अग्रिम किया है और निश्चित रूप से निश्चितता सहायक होती है, लेकिन हमने देखा है कि बाजार में मौजूद विशाल अधिशेष चलनिधि के बावजूद, उधार देने का दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि कंपनियों और कॉर्पोरेट्स से मांग की वास्तविक कमी है। बहुत अधिक पूंजीगत व्यय भी नहीं हो रहा है। यह चलनिधि वास्तव में विकास को बढ़ावा देने में कैसे परिवर्तित होती है? बैंकिंग प्रणाली में इतनी अधिक चलनिधि होने का क्या लाभ है? इसी तरह, नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) के मोर्चे पर भी, स्पष्ट रूप से आपने इसे पहले से योजनाबद्ध किया और अब घोषित किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सीआरआर कुछ हद तक 4% के पवित्र स्तर पर रहा है। क्या सीआरआर के मोर्चे पर कोई नई सोच है, जिसके कारण आप आगे बढ़े और इसे काटकर 3% कर दिया? धन्यवाद।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:
क्या मैं बस यह जोड़ सकती हूं कि आपने हमें कहीं भी यह नहीं बताया कि आपने सीआरआर में कटौती क्यों की? आरबीआई की सोच क्या थी?

संजय मल्होत्रा:
अतः, मैं पहले दूसरे प्रश्न को लेता हूं। मुझे लगता है कि मौद्रिक नीति विवरण जो मैंने पढ़कर सुनाया, उसमें उल्लेख किया गया था कि इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि हमें चलनिधि प्रदान करना जारी रखना है, और मैं चलनिधि से संबंधित आपके पहले प्रश्न पर

आऊंगा। और फिर, हमने यह भी उल्लेख किया कि यह न केवल चलनिधि में सुधार करेगा, बल्कि बैंकों के लिए फंडिंग की लागत को कम करने में भी सहायक होगा। अतः, यह दूसरा उद्देश्य है। और देखिए, पिछले 12-13 वर्षों के आंकड़े जो मैंने देखे हैं, और कोई और भी पीछे जा सकता है, सीआरआर अधिकांशत: 4% पर ही बना रहा, जैसा कि आपने सही इशारा किया। कोविड के दौरान, हमने इसे 1% कम किया था। अब, ये आरक्षित निधि मूल रूप से चलनिधि प्रबंधन के लिए रखी जाती हैं। अतः, अभी तक का अनुभव यह सुझाव नहीं देता कि शायद हमें 4% की आवश्यकता नहीं है; 3% शायद पर्याप्त हो सकता है। यह कहते हुए भी, हम नहीं जानते कि भविष्य क्या रखता है। अतः, कृपया मुझे इस संख्या से न बांधें कि हम इस 3% को बनाए रखने जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि 3% एक सहज प्रारक्षित अनुपात है। और इसलिए, चलनिधि प्रबंधन के दृष्टिकोण से, चलनिधि प्रदान करने के अलावा, यह उनकी लागतों को भी कम करेगा और उनके शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में लगभग 7 आधार अंक का सुधार करेगा; कम से कम इससे सहायता मिलनी चाहिए, यह हमारा अनुमान है। हम चलनिधि क्यों प्रदान करते हैं? ताकि बेहतर संप्रेषण हो, तेज संप्रेषण हो, और यह मूल रूप से उसी के लिए है। धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, यह निर्भर करेगा। हमने विवरण में यह भी कहा है कि यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। मौद्रिक नीति एक पर्याप्त शर्त नहीं है। यह एक आवश्यक शर्त है; हमने वह प्रदान की है। हमें विश्वास है कि यह निश्चित रूप से बेहतर ऋण वृद्धि में परिवर्तित होगी। मैं आपको कोई संख्या नहीं दे सकता। स्पष्ट रूप से, और निश्चित रूप से विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि यह ऋण के प्रवाह को निश्चित रूप से बढ़ाएगी। और इसीलिए यह चलनिधि महत्वपूर्ण है, रेपो दर में कटौती महत्वपूर्ण है। यह किस हद तक होगा और इसमें कितना समय लगेगा, यह कहना कठिन होगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगली बारी होगी ईटी नाउ से श्री अंकुर मिश्रा की।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

धन्यवाद, पुनीत सर। नमस्ते, गवर्नर सर। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपने मौद्रिक नीति में एक बयान दिया है कि आज के कदमों को उच्च आकांक्षी मार्ग की ओर ले जाने की दिशा में देखा जाना चाहिए, और आप वृद्धि की बात कर रहे हैं। आपने अपना लक्ष्य 6.5% पर बरकरार रखा है। क्या आपने जो कार्रवाई की है, उसे देखते हुए आगे कोई और संशोधन होने की गुंजाइश है, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए? और साथ ही, मैं एक बार फिर रुख के मोर्चे पर पूछूंगा, लेकिन यदि आप क्रिकेट के उदाहरण से समझा सकें, तो यह एक रोलर कोस्टर

जैसी नीति रही। उम्मीद 25 आधार अंक की थी, आपने 50 आधार अंक की कटौती की घोषणा की। इसी तरह, सीआरआर के लिए उम्मीद 50 की थी, आपने 100 की घोषणा की। लेकिन रूख के मोर्चे पर, आप क्रीज पर वापस लौट आए और कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा। तो इसे कैसे समझा जाना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:
बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, 6.5% लक्ष्य नहीं है, 6.5% वह पूर्वानुमान है जो हमने बनाया है। और आकांक्षा निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक है, 7% और 8% के बीच। हम यथासंभव तेजी से बढ़ना चाहेंगे। आपने सब कुछ कह दिया है। मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने यह बहुत अच्छी तरह से रख दिया है कि यह मौद्रिक नीति क्या है, क्योंकि भारत में यहां मौजूद हर व्यक्ति हमारी मौद्रिक नीति को नहीं समझ सकता, लेकिन वे क्रिकेट की भाषा को समझेंगे। अतः, आपने अपने दर्शकों के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अब मैं जी बिजनेस से एक्ता सूरी को आमंत्रित करूंगा।

एकता सूरी, जी बिजनेस:
नमस्ते। सर, नीति को बाजारों द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। हालांकि, मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहती हूं जो बाजार से थोड़े अलग हैं कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया। सर, मेरा पहला प्रश्न यह होगा कि पिछली नीति में हमने स्वर्ण ऋण (गोल्ड लोन) के मसौदे के बारे में बात की थी। उस नीति से लेकर आज की नीति तक, आपने कुछ बदलावों के बारे में सोचा है, क्योंकि कई लोगों को यह भी लगता है कि यदि हम सोने को गिरवी के रूप में रखने जा रहे हैं, तो संभव है कि हमारे पास स्वामित्व का कोई प्रमाण न हो, क्योंकि हमें वह अपनी मां से या किसी और से मिला हो सकता है या वह हॉलमार्क युक्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ बदलाव, आप निश्चित रूप से नियमों में परिवर्तन की सोच रहे होंगे। और दूसरी बात यह भी कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में बहुत रुचि रखते हैं। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों के संबंध में, क्या आप नियमों में कुछ बदलाव की भी सोच रहे हैं, हालांकि सरकार के पास 26% मतदान अधिकार हैं, या विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में कितनी हिस्सेदारी ले सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:
खैर, आपने सोने के ऋण पर एक अच्छा प्रश्न पूछा है, जिस पर काफी चर्चा भी हो रही थी। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए रुचि का विषय होगा, अतः आपका प्रश्न निश्चित रूप से

उचित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले, सोने के ऋण पर जो विनियम हमने जारी किए थे, वे केवल मसौदे थे, वे अंतिम नहीं थे।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अब विनियम बनाने के ढांचे के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके बारे में हमने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सभी को सूचित किया है, कि जब भी हम कोई प्रमुख परिपत्र, विनियम या निर्देश जारी करेंगे, उससे पहले हम दो कार्य करेंगे। पहली बात यह है कि हम परामर्श करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम उसका प्रभाव अध्ययन करेंगे।

अतः, यह देखते हुए कि हमने सोने के ऋण के बारे में यह विनियम पेश किया है। दूसरी बात जो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, वह यह है कि हमने जो कुछ भी पेश किया है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने केवल अपने पुराने विनियमों को समेकित किया है और हमने पुराने विनियमों को दोहराया है। हमने देखा कि कुछ विनियमित संस्थाएं विनियमों का पालन नहीं कर रही थीं क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं थी और हमने उन्हें इसके बारे में सूचित किया। इसीलिए, हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं था, लेकिन जब हमें लिखित रूप इसके बारे में टिप्पणियां प्राप्त हुईं, तो हमें पता चला। मुझे लगता है कि हम इसे आज या अधिकतम सोमवार तक जारी कर देंगे।

और आपने सोने के लिए स्वामित्व दस्तावेजों की बात की। हमने जो मसौदा जारी किया है, उसमें यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आपके पास उसका इनवॉइस नहीं है, तो आप उसकी स्व-घोषणा दे सकते हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं थी। हम इसके बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे।

दूसरी बात जो सामने आई है, वह ऋण मूल्यांकन की है कि छोटे ऋणों के लिए ऋण मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इसे भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। उन छोटे ऋणों के लिए जो 2.5 लाख रुपये तक हैं जहां संपार्श्विक सोने से आता है, वहां ऋण मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात अंतिम-उपयोग के बारे में थी कि हमें अंतिम-उपयोग की निगरानी करनी होगी। वहां भी हमने स्पष्ट किया है कि अंत-उपयोग की निगरानी केवल तभी आवश्यक होगी जब आप प्राथमिकता क्षेत्र उधार में इसका लाभ उठाना चाहें। चौथी बात जो एलटीवी (मूल्य की तुलना में ऋण) के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न थी, हमने कहा है कि एलटीवी का सिद्धांत केवल उपभोक्ता ऋणों पर लागू किया जाएगा। बाकी सब कुछ आप ऋण मूल्यांकन, अन्य आय, अन्य प्रतिभूतियों के अनुसार करेंगे; यदि आप एलटीवी अनुपात से अधिक देते हैं, तो इसे चुकौती क्षमता का आकलन करने के बाद दिया जा सकता है। पांचवीं और बहुत महत्वपूर्ण बात जो एलटीवी से संबंधित थी, वह यह कि हमने आज 75% का मसौदा जारी किया था, उस 75% को हम उन छोटे ऋणों के लिए 85% तक ले जाने जा रहे हैं जो प्रति उधारकर्ता 2.5 लाख रुपये से कम हैं, लेकिन इस 85% में ब्याज भी शामिल होना होगा। पहले यह केवल मूलधन और ब्याज का 75% था, जो ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्याज सहित 75% पर देते थे, इसीलिए उन्हें मूलधन केवल 65%, 66% और 67% ही मिलता था, लेकिन कुछ

एनबीएफसी या अन्य छोटे बैंक 75% मूलधन दे रहे थे और विशेष रूप से एकबारगी ऋण चुकौती में ब्याज सहित यह 88% तक चला जाता है क्योंकि यदि ऋण 18% का है और यदि आप इसे उल्टा गणना करें तो यह 88% तक पहुंच जाता है। 2.5 लाख रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है, यह पूरी स्पष्टता हम अपने परिपत्र में देंगे। हमें आशा है कि हम सोने के ऋण श्रेणी को काफी कुशलता से विनियमित कर सकेंगे।

संजय मल्होत्रा:

आपका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या हम विदेशी संस्थागत निवेशकों या विदेशी बैंकों की सीमा बढ़ा रहे हैं? तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान सीमा पहले से ही 74% है। इसमें 49% की सीमा स्वचालित अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत है और अतिरिक्त 25% सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से है। अतः, वे 74% तक जा सकते हैं। इसलिए, आज की स्थिति में हम इसमें किसी भी बदलाव पर विचार नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह प्रश्न कहाँ से आ रहा है कि हम इसे बदल रहे हैं। इसी से संबंधित यह है कि हम गैर-निवासियों के लिए 15% की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन मामला-दर-मामला (केस-टू-केस) आधार पर यह 15% से ऊपर भी जा सकता है। अतः, इसमें कोई तात्कालिक बदलाव होने वाला नहीं है।

हाँ, हमने इतना जरूर कहा है कि शायद आपने देखा या सुना होगा कि गैर-निवासियों के लिए 15% वाली संपूर्ण स्वामित्व संरचना या पात्रता शर्तों की हम पूरी तरह से जाँच कर रहे हैं। यह तत्काल नहीं होगा। इसमें समय लगेगा।

ये बहुत गहरे प्रश्न हैं। यदि हम क्रिकेट के उदाहरण का उपयोग करें, तो हमें इसे 20-20 मैच की तरह नहीं देखना चाहिए। हम सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या उचित है, क्योंकि एक आम व्यक्ति अपना पैसा बैंकों पर भरोसा करके रखता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक में उस प्रकार का विश्वसनीय स्वामी या प्रबंधक हो। इसके लिए हमें क्या पात्रता मानदंड रखने चाहिए, इसके लिए क्या शर्तें रखनी चाहिए, इस पर हमें सभी से बात करनी होगी। क्योंकि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मजबूत हो रही है और इसके लिए हमें अधिक बैंकों की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, जो भी आवश्यक बदलाव करने होंगे, हम करेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब मैं इकोनॉमिक टाइम्स से सुश्री संगीता मेहता से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:

मेरे अधिकांश मौद्रिक नीति संबंधी प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं वार्षिक रिपोर्ट की ओर लौट रही हूं, जो बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण थी। इसमें कई डेटा पॉइंट्स भी थे। लेकिन वार्षिक

रिपोर्ट में एक बात है, जहाँ आपने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, आरबीआई प्रकार-I एनबीएफसी, जो सार्वजनिक निधि (पब्लिक फंड्स) के बिना हैं और ग्राहकों का सामना नहीं करने वाले (नॉन-कस्टमर फेसिंग) एनबीएफसी हैं, के लिए विभेदित नियामक ढांचे (डिफरेंशिएटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) पर विचार करेगा।

संजय मल्होत्रा:
देखिए, जहां तक संभव हो नियमों को जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अनुकूलित करना हमारी नीति है, और वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख केवल उस विशेष नीति का ही निरंतरण है। मैं उप गवर्नर से अनुरोध करूंगा कि यदि वे इसमें कुछ और जोड़ना चाहें।

एम. राजेश्वर राव:
मुझे लगता है कि समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया के रूप में की जाती है और प्रकार-I वे हैं जो प्रणाली के बाहर की ओर मुख नहीं करते (जिनका बाहरी देनदारी से सामना नहीं है)। अतः, हम विनियमों पर नजर डाल रहे हैं। यह एक चल रही प्रक्रिया है, हम यह कर रहे हैं।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:
क्या इस प्रकार के एनबीएफसी के लिए फंड जुटाने पर कोई नए दिशा-निर्देश होंगे?

एम. राजेश्वर राव:
नहीं। प्रकार-I की आमतौर पर कोई बाहरी देनदारी नहीं होती है, इसलिए यह पूरी तरह से उनके आंतरिक संचय पर निर्भर करेगा।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:
क्या इस प्रकार-I की एनबीएफसी के लिए कोई नए दिशा-निर्देश आ रहे हैं?

एम. राजेश्वर राव:
हम समीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार के विनियमों की आवश्यकता है।

संजय मल्होत्रा:
इसका अर्थ है कि एक समीक्षा की जाएगी। यदि बिल्कुल आवश्यकता हुई, तो ही हम इसे करेंगे। तो, यह विनियम बनाने के हमारे ढांचे का तीसरा हिस्सा है जिसकी हमने घोषणा की थी। मैंने दो महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया था। चूंकि मैंने उसका उत्तर हिंदी में दिया था, मुझे लगता है कि सभी के लिए यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि हमने अब एक 'विनियम बनाने का ढांचा' जारी किया है। इसमें तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं: पहला, हम एक

सार्वजनिक परामर्श करेंगे। और जब मैं सार्वजनिक परामर्श कहता हूं, तो मेरा आशय केवल शब्दश: से नहीं, बल्कि भावना से भी है। अतः, हम सभी महत्वपूर्ण हितधारकों से उनके विचार प्राप्त करेंगे।

संजय मल्होत्रा:
दूसरी बात यह है कि हम यथासंभव प्रभाव विश्लेषण भी करेंगे। यह गुणात्मक (क्वालिटेटिव) हो सकता है; हर बार मात्रात्मक प्रभाव विश्लेषण करना संभव नहीं हो सकता कि इसका बैंकिंग प्रणाली, विनियमित संस्थाओं, ग्राहकों और सभी हितधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही दूसरा तत्व है। और तीसरा तत्व यह है कि हम अपने विनियमों, निर्देशों आदि की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे, क्योंकि यह गतिशील है। नीतियों को समय के साथ बदलना होता है और इसी संदर्भ में हम टाइप-I एनबीएफसी से संबंधित कुछ नीतियों की समीक्षा करने जा रहे हैं।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अब मैं ब्लूमबर्ग से श्री अनुप से अनुरोध करूंगा।

अनुप रॉय, ब्लूमबर्ग:
सर, मैं ब्लूमबर्ग से अनुप हूं। शब्दों का बहुत दिलचस्प चयन। "मौद्रिक नीतियों के पास विकास का समर्थन करने के लिए बहुत कम जगह बची है।" क्या इसका मतलब यह है कि आप उम्मीद करेंगे कि राजकोषीय प्राधिकारी शेष विकास और भारत की विकास आकांक्षाओं का समर्थन करें? और क्या इन सभी उपायों के बाद भी बैंक...

संजय मल्होत्रा:
मैं अपना काम सही ढंग से करने में विश्वास करता हूं, और हमने वह हिस्सा कर दिया है। और जाहिर है, यह उम्मीद की जाती है कि बाकी सभी भी अपना-अपना हिस्सा निभाएंगे। तो, यह कहना मेरे लिए उचित नहीं है। यह उचित नहीं होगा। मैं अपना काम करने में विश्वास करता हूं और हम यही करते रहेंगे।

अनुप रॉय, ब्लूमबर्ग:
ठीक है सर। सर, एक और प्रश्न। यदि बैंकों के लिए आपके द्वारा किए गए सभी उपायों के बावजूद, बैंक वास्तव में प्रसारण नहीं करते हैं, तो क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं? या आप किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

अंततः, हमने अपने नीति विवरण में भी यह कहा है कि मौद्रिक नीति एक आवश्यक शर्त है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है, है ना? तो, मौद्रिक नीति के पारगमन के लिए, कई अन्य चीजें भी आवश्यक हैं, जिसमें मांग का होना भी शामिल है। इसलिए यह समग्र आर्थिक स्थितियों और ऋण की भूख एवं मांग पर निर्भर करेगा। केवल तभी बाजार की शक्तियों, अंततः... देखिए, हमें इसे बाजार की शक्तियों पर छोड़ना होगा। हम यह विनियमित नहीं कर सकते कि 'नहीं, आप ऋण दो' या 'आप दरें कम करो'। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह एक बाजार है। हमारा मानना है कि हमारे बाजार गहरे हैं। ऋण बाजारों में इतने सारे बैंक हैं, इतने सारे एनबीएफसी हैं, वैकल्पिक निवेश फंड हैं जो अब ऋण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, निजी ऋण है, इसलिए बाजार की ताकतें निश्चित रूप से ऋण की मांग के आधार पर कीमतों को निर्धारित करने में सक्षम होंगी।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। मनी कंट्रोल से हंसिनी।

हंसिनी कार्तिक, मनी कंट्रोल:

धन्यवाद। हाय, मैं मनी कंट्रोल से हंसिनी हूं। मेरा प्रश्न बैंकिंग प्रणाली की सेहत से संबंधित है। सर, आपने अपने आज के भाषण में उल्लेख किया था कि आप आश्वस्त हैं, आप बैंकिंग प्रणाली की सेहत को लेकर काफी आत्मविश्वासी हैं। क्योंकि एक निजी क्षेत्र के बैंक में, जहां ऑडिटरों ने हाल ही में कुछ घटनाक्रमों को संभावित धोखाधड़ी के रूप में योग्य ठहराया है, क्या वह मामला आरबीआई तक पहुंचाया गया है? आप उस पर किस प्रकार की कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? और लगभग 4 महीने हो गए हैं जब आरबीआई ने बैंक के पक्ष में एक बयान जारी किया था कि जमा राशि सुरक्षित है। सर, वर्तमान स्थिति का आपका आकलन क्या है?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, सामान्यतः हम व्यक्तिगत बैंकों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली बहुत ही मजबूत है। और मैंने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी घटनाएं या प्रसंग—मैं इन्हें यही कहूंगा—होते रहते हैं। जब तक ये दुर्लभ हों और सीमित हों, तब तक इनसे हमें अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि बैंक ने अपने लेखांकन और अन्य प्रथाओं में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। और समग्र रूप से, मुझे लगता है कि बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि यदि वे आवश्यकता अनुसार अधिक विस्तार से जानकारी देना चाहें।

स्वामीनाथन जे.:

सर, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने इस विशेष संस्था की वर्तमान स्थिति का सारांश प्रस्तुत कर दिया है। आपकी याददाश्त होगी कि पिछली मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति) की प्रेस वार्ता में भी हमने 2-3 बातें कही थीं, जिनका इस समय तक पालन कर लिया गया है।
पहला, हमारी प्राथमिकता यह थी कि लेखांकन उचित ढंग से किया जाए, सभी विसंगतियों का हिसाब आंतरिक और बाहरी ऑडिट दोनों द्वारा समर्थित होकर किया जाए, और इसे चौथी तिमाही में ही समाहित किया जाए। तो, यह बैंक द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है।
दूसरा, हमने कहा था कि फोरेंसिक ऑडिट और जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि लोगों को उत्तरदायी ठहराया जा सके और धोखाधड़ी की जांच पूरी हो जाए, जिसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां आगे की कार्रवाई संभालें। तो, यह भी पहले ही पूरा कर लिया गया है।
और तीसरा, निश्चित रूप से, हमारी प्राथमिकता हमेशा यह सुनिश्चित करना रही है कि किसी भी ग्राहक को कोई नुकसान या असुविधा न हो। यह सुनिश्चित कर लिया गया है और इस प्रकार की घटनाओं से कोई प्रणालीगत प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ है।
और चौथा, हमने यह भी कहा है कि हर संकट हमें कुछ सबक देता है। इसलिए, हम इन सबकों के आधार पर अपने पर्यवेक्षी उपकरणों को और तेज करते हैं और अपने पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को अंशांकित करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस प्रकार के सावधान करने वाले निशान (रेड फ्लैग्स) की तलाश करेंगे ताकि हम उन्हें बहुत पहले से भांप सकें।
अंत में, उत्तराधिकार योजना के संदर्भ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड और प्रबंधन ने आपको अपनी अद्यतन स्थिति साजाकी हैं। तो, जैसा कि गवर्नर ने कहा, जो कुछ भी पिछले 3 महीनों में होना था, वह कमोबेश पटरी पर है। और मुझे यकीन है कि यह तुरंत नहीं तो बहुत जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएगा, और हम न केवल इसकी बल्कि पूरी प्रणाली की निगरानी करते रहेंगे।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद, सर। यदि मुझे एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। जमा राशियों के मोर्चे पर, प्रसारण का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक क्या निर्णय लेते हैं।

संजय मल्होत्रा:

आप किसी और का समय ले रही हैं, इसलिए रुकिए। यदि आपका प्रश्न किसी और द्वारा नहीं लिया जाता है, तो हम वापस आ सकते हैं।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद। धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास 'मिंट' से गोपिका होंगी।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:
धन्यवाद, सर। शुभ अपराह्न, गवर्नर। आपने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 3.7% कर दिया है। तो, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आपका मुद्रास्फीति अनुमान क्या होगा? क्या आपने इसे विवरण में उल्लेख किया था?

संजय मल्होत्रा:
6.5%... क्षमा करें, 4.5%।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:
ठीक है। तो, आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह 4% से ऊपर जाएगा?

संजय मल्होत्रा:
हाँ।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:
और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर भी, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसे सितंबर से नवंबर तक चरणबद्ध किया जाएगा। वैश्विक स्थिति क्या है? मुझे पता है कि आप बैंकों को एक स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर वातावरण बदल जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए? मेरा मतलब है यदि कोई जोखिम हो। तो फिर आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सीआरआर...?

संजय मल्होत्रा:
हमारे पास पर्याप्त उपकरण हैं। देखिए, मौद्रिक नीति या चलनिधि के लिए सीआरआर एकमात्र उपकरण नहीं है। आपके पास खुले बाजार की कार्रवाई हैं, स्वैप्स हैं। और आपके पास वीआरआर और वीआरआरआर भी हैं। इसलिए, यदि चलनिधि का प्रबंधन करना हो–जिसकी हमें वास्तव में आज यह महसूस नहीं हो रही है कि उनमें से किसी चीज को उल्टा करने की आवश्यकता होगी–तो हमारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपकरण मौजूद हैं।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:
हंसिनी का निजी क्षेत्र के ऋणदाता से संबंधित प्रश्न? आरबीआई बोर्ड से जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेगा? अब तक हमने उस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं देखी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ उसके लिए बोर्ड भी जिम्मेदार है?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, व्यक्तिगत... तो, आप इंडसइंड बैंक आदि की बात कर रही हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रबंध निदेशक और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। और उनके त्यागपत्र में 'नैतिक जिम्मेदारी' लेने का उल्लेख है। तो, मुझे लगा कि यह पर्याप्त होना चाहिए। क्या आप उम्मीद करती हैं कि सभी बोर्ड सदस्य...? मेरा मतलब है, आप किस ओर इशारा कर रही हैं? मुझे लगता है, आप जानती हैं कि प्रबंध निदेशक और सीईओ, जो बोर्ड के सदस्य भी हैं, यदि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो यह बोर्ड स्तर पर ही है।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

सर, क्षमा करें, बीच में टोकने के लिए। यहां तक कि सेबी ने भी अब एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ प्रकार का भेदिया व्यापार हुआ हो सकता है और नोटिस जारी किए गए हैं। बैंक का दावा है कि उनके साथ धोखेधड़ी हुई है। तो, सर, मैं यह समझना चाहता हूं। क्या वे विशेष रूप से आप तक पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉल में उल्लेख किया था कि धोखेधड़ी की स्थिति के कारण वे विनियामक या जांच एजेंसियों तक पहुंचेंगे? तो, मेरा मतलब है कि यह किसी एक बैंक से संबंधित है, लेकिन यह विश्वास की प्रणाली का मामला है।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, यदि अन्य आपराधिक कार्य हुए हैं, तो कानून अपना रास्ता तय करेगा। कृपया आश्वस्त रहें। और यदि मामले में आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो आरबीआई अपने कर्तव्य में चूक नहीं करेगा। इसे इतना ही रहने दें।

संजय मल्होत्रा:

नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां अन्य लोग भी हैं, आपने अपना प्रश्न पहले ही पूछ लिया है।

पुनीत पंचोली:

सुनने के लिए धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

और चलिए किसी घटना से पहले ही अनुमान नहीं लगाते। चलिए इसके बारे में अटकलें नहीं लगाते।

पुनीत पंचोली:
बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। अगले, हमारे पास 'द हिंदू बिजनेस लाइन' से श्री पियूष होंगे।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिजनेस लाइन:
नमस्ते गवर्नर, उप गवर्नर महोदय। धन्यवाद, पुनीत जी। तो, अरक्षित ऋणों पर, आपने कहा कि वैयक्तिक ऋण में दबाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन एमएफआई में दबाव बना हुआ है। तो, क्या आप इसे हल करने के लिए कोई अन्य उपाय करने की योजना बना रहे हैं? इसके अलावा, कुछ पेमेंट बैंकों ने लगभग 18 महीने पहले लघु वित्त बैंक (एसईबी) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। फिर 2 लघु वित्त बैंकों ने अब सार्वभौमिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। क्या कोई समयसीमा है, सर? अन्य सभी मामलों में आरबीआई के पास अनुमोदन की एक समयसीमा होती है। तो, क्या कोई समयसीमा है जिसके भीतर आप अनुमोदन देंगे? आपने विकासात्मक और विनियामक नीति पर कोई बयान जारी नहीं किया?

संजय मल्होत्रा:
आप तीन प्रश्न पूछ रहे हैं।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिजनेस लाइन:
यह हमारा स्पष्टीकरण है। हमें वे उत्तर नहीं दिखाई दिए।

संजय मल्होत्रा:
स्पष्टीकरण? यदि बात वैसी नहीं है तो मैं क्या स्पष्ट करूं? लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि हम कार्यों में विश्वास करते हैं, केवल बयानबाजी में नहीं। हमारे पास पहले से ही काफी काम है। इसलिए, हम पहले... हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास कई मसौदे हैं–जैसा कि आपने गोल्ड लोन का उल्लेख किया और अन्य भी हैं। भगवान का शुक्र है कि आप मुझसे उन बारे में नहीं पूछ रहे हैं। आप मुझसे उन मसौदों के बारे में और अधिक मांग रहे हैं। इसलिए, हम बजाय इसके कि और अधिक बोलें, यह कोशिश करेंगे कि हमने जो पहले से ही प्रक्रियाधीन है, जो हमने वादा किया है, उसे मजबूत करें। इसलिए, यदि बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बोलना जरूरी नहीं है, है न? आपके अन्य प्रश्न क्या थे? बैंक लाइसेंस? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी समयसीमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास आंतरिक समयसीमा नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा बताए गए सभी आवेदनों पर काम प्रगति पर है और बहुत जल्द आप हमारे निर्णय देखेंगे। हमने उनमें से एक पर पहले ही निर्णय व्यक्त कर दिया है, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि वह पहले से ही सार्वजनिक है, और बाकियों पर भी हम जल्दी निर्णय लेंगे।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिजनेस लाइन:
किस आवेदन को अस्वीकार किया गया था?

संजय मल्होत्रा:
यह सामने आने वाला है। एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में यह जारी की जाएगी। आपको पता चल जाएगा।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिजनेस लाइन:
क्या यह आज जारी होगी?

एम. राजेश्वर राव:
यह जारी होगी। हम प्रयास करेंगे।

पीयूष शुक्ल, द हिंदू बिजनेस लाइन:
सर, लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) के संबंध में, क्या आप कोई और उपाय करेंगे? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:
एमएफआई के लिए कोई विशिष्ट विनियामक उपाय योजनाबद्ध नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। एमएफआई से संबंधित कुछ और है, लेकिन वह इस विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है। पर्यवेक्षण पक्ष पर, यदि आप एमएफआई पर कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि वे वास्तव में अपने व्यवसाय को पुनः अंशांकित कर रहे हैं, तो हम पर्यवेक्षण के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप एमएफआई पोर्टफोलियो पर कुछ जोड़ना चाहें, तो मुझे लगता है कि यह सहायक होगा।

स्वामीनाथन जे.:
धन्यवाद, सर। मुझे लगता है कि यह बात पहले ही मौद्रिक नीति समिति के विवरण में स्पष्ट की जा चुकी है कि इस विशेष खंड में प्रमुख रूप से कार्य करने वाली संस्थाओं की पहचान कर ली गई है, उन्होंने अपने व्यवसाय मॉडल को पुनः अंशांकित कर लिया है और अपनी वसूली पद्धतियों को मजबूत किया है। आपने उस पुनः अंशांकन के कारण उस पोर्टफोलियो में सिकुड़न भी देखी है। तो, हो सकता है कि समय के साथ, अगली कुछ तिमाहियों में, यह स्थिर हो जाए, जैसा कि हमने अन्य दो खंडों में देखा था जहां असामान्य वृद्धि हुई थी। हमने कुछ कदम उठाए और फिर यह धीमी हो गई। तो, यह भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह समग्र आर्थिक स्थितियों और आय के स्तर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एमएफआई की बही सबसे संवेदनशील खंड के पास हैं। इसलिए, हमें इसे ध्यान में रखना होगा, इसे सामान्य होने के लिए

थोड़ा अधिक समय देना होगा, लेकिन हम उन आंकड़ों पर नजर रखते रहेंगे। जैसा कि गवर्नर ने कहा, इनमें से किसी भी खंड के लिए इस समय किसी विनियामक कार्रवाई या उपाय की आवश्यकता नहीं है।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। सर, आपकी अनुमति से अंतिम 3 प्रश्न।

संजय मल्होत्रा:
जी हाँ।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। अगले, हमारे पास पीटीआई से श्री आशीष आगाशे होंगे।

आशीष आगाशे, पीटीआई:
बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। सर, यह अरक्षित ऋण पर पीयूष के प्रश्न का अनुवर्ती है। चूंकि ऋण वृद्धि को बढ़ावा देना एक स्पष्ट इरादा है, तो क्या हमें नवंबर 2023 के जोखिम भार आदेश पर कुछ वापसी की उम्मीद करनी चाहिए? और दूसरा...

संजय मल्होत्रा:
इस मामले में जो कुछ किया जाना था, वह कर दिया गया है। जो कुछ था, देखिए, कोविड से पहले जो जोखिम भार थे, कोविड के दौरान कुछ छूट दी गई थी जिसे वापस ले लिया गया। और बस इतना ही। यदि कोई कसाव हुआ था, तो उसे भी वापस ले लिया गया है। इसलिए, जोखिम भार पर कुछ और नहीं है।

आशीष आगाशे, पीटीआई:
और सर, क्रिप्टो मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, क्या कोई चर्चा हुई है? हालांकि आरबीआई का रुख पहले से ही स्पष्ट रहा है, लेकिन दिए गए...

संजय मल्होत्रा:
क्रिप्टो के संबंध में अब तक कोई नई प्रगति नहीं हुई है। सरकार में एक समिति है जो इसकी देखरेख कर रही है। निश्चित रूप से, आप जानते हैं, हम क्रिप्टो को लेकर चिंतित हैं क्योंकि यह वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति आदि को बाधित कर सकता है।

आशीष आगाशे, पीटआई:
धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। श्यामा, दूरदर्शन, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:
नमस्कार सर। सर, आपकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज सामने आई है और यह बहुत अच्छी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आमतौर पर आरबीआई को रूढ़िवादी माना जाता है। तो, अपनी कहानी स्वयं बताने का यह विचार कहां से आया?

संजय मल्होत्रा:
मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों से पूछना होगा जो इसमें शामिल थे, इसलिए शायद उप गव्रनर रवि शंकर इस विचार के उद्गम पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं।

टी. रबी शंकर:
जी, यह 'आरबीआई@90' की उन घटनाओं के संदर्भ में आया जो हमने आयोजित की थीं। जैसे-जैसे हमने उन कार्यक्रमों को आयोजित करना जारी रखा, और हमने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, अन्य केंद्रीय बैंकों आदि के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए, तो इस प्रक्रिया में हमें जो प्रतिक्रिया मिली, वह यह थी कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनी कार्यप्रणाली, विशेष रूप से आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत गुंजाइश है। आम जनता को मुद्रा, कीमतों और मौद्रिक नीति के बारे में एक विचार तो है। हमारा उद्देश्य आरबआई की कार्यप्रणाली को आम जनता के सामने अधिक खोलना था और उसी संदर्भ में, हमने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में सोचा। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का विचार यह दिखाना है कि आरबआई क्या करता है, वह भी ऐसी भाषा और दृश्य रूप में जो एक औसत व्यक्ति समझ सके। धन्यवाद।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:
तो, केवल एक एपिसोड अभी तक सामने आया है। कुल कितने एपिसोड हैं और वे कब-कब आएंगे?

टी. रबी शंकर:
कुल 5 एपिसोड हैं। वे एक के बाद एक आते रहेंगे।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद। धन्यवाद, सर। अंत में, हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस से श्री हितेश होंगे।

हितेश व्यास, इंडियन एक्सप्रेस:
शुभ अपराह्न, सर। सर, आपकी वार्षिक रिपोर्ट में आपने उल्लेख किया है कि आपकी कार्यसूची में से एक मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन करना है, और इसके हिस्से के रूप में आप प्रणाली चलनिधि के इष्टतम स्तर पर पुनर्विचार करेंगे। तो, वह चलनिधि स्तर कौन सा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं ताकि संचरण प्रभावी हो सके?

संजय मल्होत्रा:
अध्ययन उन्हीं पहलुओं को देखेगा। इसलिए यह रिपोर्ट में शामिल है। और यदि मुझे इसका उत्तर पहले से पता होता, तो यह रिपोर्ट में नहीं होता। अध्ययन उन विवरणों में जाएगा कि चलनिधि को कैसे बनाए रखा जाए ताकि मौद्रिक नीति को मुद्रा बाज़ार और क्रेडिट बाज़ार में स्थानांतरित या अनुवादित किया जा सके।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:
गवर्नर, मेरे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसलिए यदि मुझे अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

संजय मल्होत्रा:
कितने बचे हैं? केवल दो?

पुनीत पंचोली:
सर, वास्तव में 3 हैं।

संजय मल्होत्रा:
ठीक है, हम अंतिम 3 लेते हैं।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:
धन्यवाद। संचरण के संदर्भ में, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक अपनी जमा दरों को कैसे देखते हैं और हम आज कहां हैं। हमने जमा मोर्चे पर ज्यादा सुधार नहीं देखा है। बैंक

जमा दरों को उच्च बनाए हुए हैं क्योंकि प्रणाली में जमा के लिए संघर्ष अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। तो, सर, आप इस विशेष पहलू को कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? आप जमा पक्ष पर किस प्रकार के संचरण की उम्मीद करते हैं? उधार दरों के पुनः अंशांकन के लिए आप इसे कितनी जल्दी होने की उम्मीद करते हैं?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है और मैंने इसका उत्तर भी दे दिया है। लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, फरवरी में हमने जो 25 आधार अंक की कटौती की थी, उसके मुकाबले जमा दरों में औसतन 27 आधार अंक की कमी आई है, लेकिन इसमें एक अंतराल है। यह रातों-रात नहीं होगा। आस्ति पक्ष पर, हमारी ऋण पुस्तक का लगभग 45% बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा है, जो तुरंत स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन जमा पक्ष पर, ऐसा कोई तंत्र नहीं है। इसके बावजूद, इसमें अंतराल है। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसमें अंतराल होता है। इसके बावजूद, 25 आधार अंक के मुकाबले जमा पक्ष पर पहले ही 27 आधार अंक का संचरण हो चुका है। अंततः, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यह अंतराल के साथ होगा, यह होगा। यह वही है जो हमने देखा है। पिछले दो चक्रों में, चाहे वह कसाव हो या ढील, हमने देखा है कि यह 6 से 9 महीने के अंतराल के साथ होता है। और इस बार भी यही होगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। मैं श्री ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू से अनुरोध करता हूं।

ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू:

शुभ अपराह्न, सर। सर, हमने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। वर्तमान में युद्धविराम है। उस अवधि के बाद अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि अब दोनों पक्षों ने दुनिया भर में अपने दृष्टिकोण रखते हुए अपने रुख को और सख्त कर लिया है। और दूसरा, कोविड के संबंध में, कुछ मामलों में वृद्धि देखी गई है। क्या वहां कोई चिंता का विषय है, सर? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

कोविड वर्तमान में चिंता का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि यह वायरस में से एक बन गया है। उम्मीद है कि आप जानते हैं कि यह ऐसा ही बना रहेगा। जो संघर्ष हमारा हुआ था, या झड़प कहें, या जो भी आप उसे कहना चाहें, उसका आर्थिक गतिविधियों पर बहुत ही सीमित, नगण्य प्रभाव पड़ा। हां, उन कुछ दिनों के लिए इसका कुछ प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से उत्तर भारत में। हवाई अड्डे बंद होने से वायु यात्री यातायात निश्चित रूप से कम हुआ। लेकिन कोई

प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आदि नहीं हुआ। इसलिए, इसका आर्थिक गतिविधि, विकास या मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में कुछ दिनों के लिए कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया है। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई सार्थक या प्रमुख प्रभाव नहीं पड़ा है।

पुनीत पंचोली:
धन्यवाद, सर। और अंत में, द इन्फॉर्मिस्ट से श्री आर्यन।

आर्यन खन्ना, द इन्फॉर्मिस्ट:
धन्यवाद, सर। मैं द इन्फॉर्मिस्ट से आर्यन हूं। तो, यह प्रश्न वास्तव में गवर्नर महोदय के साथ-साथ उप गवर्नर शंकर सर और गुप्ता जी के लिए भी है। अतीत में यह देखा गया है कि ऊर्ध्व प्रतिफल वक्र ने कार्पोरेट्स तक दरों में कटौती के संचरण को बाधित किया है।

संजय मल्होत्रा:
किसने बाधित किया?

आर्यन खन्ना, द इन्फॉर्मिस्ट:
ऊर्ध्व प्रतिफल वक्र ने, सर। आज मौद्रिक नीति समिति की कार्रवाई और आरबीआई की कार्रवाई ने इस यील्ड कर्व को और भी खड़ा कर दिया है। तो, क्या इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? और दूसरा, चलनिधि प्रबंधन ढांचे के संदर्भ में, बाजार में कुछ चर्चाएं हुई हैं, क्या इसके मसौदे पर कोई समयसीमा है, सर? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:
देखिए, चलनिधि प्रबंधन ढांचे पर हमारे पास कोई निश्चित समयसीमा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे यथाशीघ्र करना चाहेंगे। ये जटिल मामले हैं जिन्हें विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में हमारे देश में मुद्रा बाजार एक प्रकार का एकीकृत नहीं है। वहां तीन अलग-अलग बाजार हैं। प्रतिभागी अलग-अलग हैं, संपार्श्विक और गैर-संपार्श्विक। इसलिए, संचरण के दृष्टिकोण से, हमें इन मुद्दों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं, और मैं वास्तव में इस पर कोई समयसीमा नहीं दे सकता। सबसे पहले यील्ड कर्व पर, और आप चलनिधि प्रबंधन ढांचे पर भी इसे पूरक कर सकते हैं।

टी. रबी शंकर:
जी, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल कई कारकों से प्रभावित होते हैं। उन कारकों में से एक मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति की अपेक्षाएं हैं, तथा चलनिधि एक

अन्य कारक है। लेकिन यह विशिष्ट क्षेत्रों में मांग आदि पर भी निर्भर करता है। आम तौर पर, आप यह देखते हैं कि मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया में, अल्पकालिक छोर दीर्घकालिक छोर की तुलना में शीघ्र समायोजित होता है। इसलिए, जब दरों में कटौती की जाती है, तो वक्र ऊर्ध्व होने की प्रवृत्ति दिखाती है; और जब दरें बढ़ाई जाती हैं, तो वक्र समतल होने की प्रवृत्ति दिखाती है। यह होता है, लेकिन बाजार समय के साथ इनमें समायोजन कर लेता है। इसलिए, जैसा कि हमने कहा, हम विदेशी मुद्रा में किसी विशेष दर को लक्षित नहीं करते हैं। इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड्स में भी कोई निश्चित दरें नहीं होती हैं, और बाजार अपना स्वयं का स्तर खोज लेगा। यदि बाजार को लगता है कि यह यथोचित स्तर की तुलना में अत्यधिक खड़ा है, तो वे इसका समायोजन करेंगे। अतः हम ऐसे समायोजनों के लिए इसे बाजार पर छोड़ देंगे। चलनिधि के संबंध में, मुझे लगता है कि जैसा कि गवर्नर महोदय ने कहा, हम इस पर विचार कर रहे हैं; एक बार आंतरिक जांच पूरी हो जाने पर, हम उस ढांचे को जारी करेंगे। धन्यवद।

आर्यन खन्ना, द इन्फॉर्मिस्ट:

बहुत-बहुत धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। इसके साथ ही हम इस पत्रकार वार्ता का समापन करते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने और इसे अत्यंत संवादपरक बनाने के लिए रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूं। यहां उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं आप सभी को एक सुखद दिन की कामना करता हूं।